Title : Regarding need to clear the proposal of the Government for Uttar Pradesh for inclusion of certain castes in the list of SCs/STs.

(xiii) **Need to clear the proposal of the Government for Uttar Pradesh for inclusion of certain castes in the list of SCs/STs**

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : अध्यक्ष महोद्य, गत सालों में कुछ जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कराने हेतु विभिन्न राज्यों व संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा विधिवत सर्वे करा कर, अपनी संस्तुति के साथ केन्द्र सरकार के पास राज्य सरकारें भेजी हैं, पर केन्द सरकार उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल करने के संबंध में प्रस्तावित निर्णय लेने में देरी के कारण लाखों लोगों को सुविधा मिलने में देरी हो रही है। मेरा मानना है कि जिन जातियों को अनुसूचित जाति में बहुत पहले ही शामिल कर लेना चाहिए था, वे अभी भी अधर में लटक रही हैं, अन्य राज्यों में उनमें से कई जातियां पहले से ही अनुसूचति जाति/अनुसूचति जनजाति में शामिल हैं पर कुछ राज्यों में वे आज भी उक्त सूची में शामिल नहीं है। आर्थिक रूप से काफी पिछ्ड़ी जातियां और भी पिछ्ड़ती जा रही हैं, इस तरह उन जातियों के लाखों लोगों के साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि वे जातियां सरकारों द्वारा जारी आरक्षण संबंधी सुविधाओं से वंचित हैं। उत्तर प्रदेश की कुछ जातियां- केवट, न्िाद, बिंद धीवर, धीमा, मछुआ, कश्यप व चिक, चाक, हिन्दू चिकवा को भी इसी प्रकार अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने के प्रस्ताव को केन्द्र सरकार की अभी तक मंजूरी न मिल पाने के कारण उन जातियों के हजारों लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आर्थिक, सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछ्ड़ी ऐसे जातियों को जिनको केन्द्र सरकार से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु राज्य सरकारों से अनुशंसा प्राप्त हो चुकी हैं, को अविलम्ब अनुसूचित जाति/जनजाति की सूची में सम्मिलित करने का क्ट करें।